>

Title: Regarding statement by the Minister of Defence on the report by Shri Shyam Saran, Chairman, National Security Advisory Board.

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): माननीय सभापति महोदय, कल शाम को मैंने इसी सदन में प्रश्न उठाया था जो राष्ट्रीय सुरक्षा का एक गंभीर मुद्दा है कि चीन ने हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। मैंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया था जो कि प्रधानमंत्री जी के विशेष दूत श्री श्याम संरन ने लद्दाख के भ्रमण के बाद उनको सौंपी थी। मैंने यह मांग की थी, शायद गलती की थी क्योंकि रक्षा मंत्री का इस तरह बयान आया है। मुझे लगा कि गलती मैंने इसलिए की क्योंकि जो बयान रक्षा मंत्री जी का आया है उसमें बातें छुपाई गई हैं और सच्चाई को दबाया गया है। हम सब जानते हैं, चूंकि अंग्रेजी भाषा ऐसी भाषा है जिसमें अगर कुछ बात कह दी जाए तो तथ्यात्मक दृष्टिकोण से नहीं कह सकते कि यह गलत है लेकिन सच्चाई छुपाने के लिए वह काफी है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए सच्चाई को छुपाने का प्रयास किया गया।

महोदय, मैंने गौर से इस स्टेटमेंट को देखा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान एक खास वाक्य की ओर दिलाना चाहता हूं जो उनके बयान में है:-/

> "I would like to state categorically that Shri Shyam Saran has not stated in this report that China has occupied, or has denied access to India to any part of Indian territory."

20.42 hrs (Shri P.C. Chacko *in the Chair*)

China has not occupied or denied access to India to any part of Indian territory. On the face of it, ऐसा लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। अब चीन ने लिखित क्या दिया है कि आप नहीं जा सकते हैं। चीन ने नोट पर बल दिया है कि आप नहीं जा सकते हैं, चीन ने सच्चाई में, यथार्थ में जमीन पर यह कर दिया है। यह जो बात है इसे मंत्री महोदय अपने बयान में छुपा गए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल की है और शायद चीन की दूसरी है। ईस्टर्न लद्दाख, जिस इलाके के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, चीन लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल उसे मानता है जो उस समय के चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने हमारे प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को पत्र लिखकर 7 जनवरी, 1959 को भेजा था। उसमें उन्होंने एक लाइन का जिक्र किया था, चाइनीज मानते हैं कि यही लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल है। हमारे यहां सरकारी पदाधिकारियों का चाइना स्टडी ग्रुप है, इसमें मिलिट्री पदाधिकारी भी हैं। इस ग्रुप ने 1976 में तय किया था कि 1962 की लड़ाई की सच्चाई के आधार पर लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। हम इसे लाइन आफ कंट्रोल नहीं कहते हैं जैसे पाकिस्तान की सीमा को लाइन आफ कंट्रोल कहते हैं। यह लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल है जहां दोनों आर्मीज 1962 युद्ध के बाद आमने सामने रही, यह वही लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल है। उस मंत्रालय को छोड़े बहुत दिन हो गए हैं, मैं याद्दाश्त से बोल रहा हूं कि लाइन आफ कंट्रोल हमारा है। यह उनका लाइन आफ कंट्रोल 1959 का है जो इंडिया-चीन युद्ध 1962 में हुआ था। यह उसके पहले का है। उसके बाद बहुत सारे एग्रीमैन्ट्स हुए, 1966 का एग्रीमैन्ट हुआ और 2005 का एक प्रोटोकोल है, जिस प्रोटोकोल के अनुसार अगर पैट्रोलिंग करते समय दोनों देशों की आर्मी आमने-सामने आ जाए तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, इसके बारे में 2005 का प्रोटोकोल है। उसमें एक तो यह है कि हिंसा नहीं करेंगे, एक-दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, विदड्रा कर जायेंगे, अपने देश के प्रतिनिधियों को बतायेंगे, वे इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और वह यह है कि यह जो इलाका है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन न हम करेंगे और न वे करेंगे। 2005 का बॉर्डर प्रोटोकोल यही कहता है। अभी हाल में अप्रैल में जब डिपसांग में चीनी सेना घुस आई थी, हम सब जानते हैं कि वे 20 या 25 किलोमीटर हमारी भूमि के अंदर, सीमाओं के अंदर आ गये थे और उन्होंने कैम्प लगा दिया था, कैम्प लगाया था, एक स्ट्रक्चर बनाया था, जो 2005 के बॉर्डर प्रोटोकोल का खुला उल्लंघन था और हम कुछ सकपकाये रहे, हम हेजिटेट करते रहे, हमने इसका मुकाबला नहीं किया और बहुत दिनों के बाद जब उनकी मर्जी में आया तब वे वहां से हटे, वहां से वापस गये। हमने उन्हें हटाने के लिए कुछ नहीं किया। वे स्वयं आये, हमें एक संदेश दिया और वह संदेश क्या था, वह संदेश यह था कि हम जो चाहे वह कर सकते हैं और अगर तुममे हिम्मत है तो हस्तक्षेप करके देख लो और हमने हिम्मत नहीं दिखाई जब उनकी मर्जी में आया, तब वे वहां से गये।

महोदय, मैं मंत्री महोदय से बिल्कुल स्पष्ट जानना चाहता हूं कि यह जो चाइना का इनकर्शन हुआ, मेरी जानकारी यह है कि एक डिपसांग बल्ज है, जो मैप में इस तरह का इलाका है, जिसे बल्ज कहते हैं। वह हमारा इलाका था, आज वह हमारे पास नहीं है और मैं गम्भीरता और जिम्मेदारी के साथ मंत्री महोदय से आज इस सदन के फ्लोर पर जानना चाहता हूं कि क्या डिपसांग बल्ज आज भारत के नियंत्रण में है या हम उसे खो चुके हैं? आप छोड़ दीजिए 570, 540 या 640 स्कवायर किलोमीटर्स है या कितना था, कल मैं गलत था। कल मैंने कहा था कि 640 स्कवायर किलोमीटर्स चीन ने कब्जा कर लिया है। जब मैंने इसकी तहकीकात की तो मुझे पता चला कि उन्होंने जो हरकत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर की है, उसमें एक्चुअली 750 स्कवायर किलोमीटर्स का इलाका उन्होंने ऐसा कर दिया है कि भारत की आर्मी के पैट्रोल वहां नहीं जा सकते और उन्होंने इसी तरह 2005 के प्रोटोकोल का वायलेशन करते हुए क्या किया है, एक ट्रैक जंक्शन है और मैं मंत्री महोदय से इसके बारे में जानकारी चाहता हूं कि दौलत बेग ओल्डी के पास एक ट्रैक जंक्शन है, उस ट्रैक जंक्शन में उन्होंने एक सड़क बनाई है, जो मोटरेबल है। चाइना की आर्मी मोटराइज्ड ट्रूसपोर्ट में उस रोड का इस्तेमाल करती है और उस रोड का असर यह पड़ा है कि हमने जैसा कहा कि 750 स्क्वायर किलोमीटर्स जिसमें हमारी सेना पैट्रोलिंग कर सकती थी, उससे आज के दिन हम वंचित हैं। यह कैसे हुआ, कब हुआ? इसके अलावा जो चुमार इलाका है, वहां पर भी हम पैट्रोलिंग करते थे। वहां पर प्वाइंट्स मैप में दिए हुए हैं - 10, 11, 11ए और 13 जहां हम जाते थे, हमारी सेना पैट्रोलिंग करते हुए जाती थी, परंतु आज हम वहां पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि चीन ने रोक दिया है, उसकी फौज वहां पर खड़ी है। अब वह वहां क्यों खड़ी है, क्योंकि एक पाकीनाला है, उस पाकीनाला से आगे जाने से उन्होंने हमें रोक दिया है तो हम उन प्वाइंट्स पर नहीं जा सकते हैं।

फिर हम सब जानते हैं कि एक पैंगोंग चो लेक है, जिसमें एक स्वीजाप एरिया है, वहां पर चीन आज डॉमिनेट कर रहा है, उसने all along the Line of Actual Control अपनी पोज़िशंस को स्ट्रेंथन किया है। वह ज्यादा आक्रामक भूमिका में आ गया है। बार-बार हमारी भूमि के अंदर, सीमा के अंदर जो incursion हो रहा है, वह इसीलिए हो रहा है, क्योंकि चीन की फौज ने वहां पर ताकत बनाई है और हमने ताकत नहीं बनाई है। इसीलिए प्रधान मंत्री जी ने श्री श्याम सरन, जो उनके विशेष दूत हैं, उनको भेजा कि लद्दाख का जो एरिया है, वहां से ले कर नॉर्थ-ईस्ट तक आप जाइए और पूरे Line of Actual Control को देखिए। यह सही है, जैसा

मंत्री महोदय ने कहा कि उसमें यही मुद्दा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से आप देखिए। हम सब जानते हैं, हम लोग जब सरकार में थे, तो हमने शुरूआत की थी कि वहां इंफ्रास्टक्चर मज़बूत हो। मुलायम सिंह जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने कोशिश की थी कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मज़बूत हो। लेकिन हमसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए, चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत कर लिया और हम अभी भी बहुत पीछे हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है? चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, उसको सुविधा ज्यादा है। वे जहां चाहें वहां आसानी से जा सकते हैं। हमारे पास में साधन नहीं हैं। अभी भी हम बहुत सारे इलाके में mule trains पर डिपेंड करते हैं। जहां वे कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं, वहां हमको पहुंचने 15 दिन लगते हैं। सब मिला-जुला कर श्याम शरण जी को यह देखने के लिए भेजा गया कि ईस्टर्न लद्दाख का यह जो इलाका है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें और सब बातों को देखें। मेरी अपनी जानकारी है और मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि श्याम शरण 2-9 अगस्त, 2013 को गए थे और लौट कर उन्होंने एक रिपोर्ट सब्मिट की थी, जो इनके मंत्रालय को 2nd September, 2013 को प्रधान मंत्री कार्यालय से भेजा गया। लगभग एक महीने के बाद। लेकिन मैं जानता हूँ कि श्याम शरण जी ने लौटने के बाद व्यक्तिगत रूप से प्रधान मंत्री जी से 10 अगस्त को मिल कर इन सारी बातों की चर्चा की थी कि कैसे यह पूरा एरिया जो है, उस इलाके में there is Chinese domination at Line of Actual Control. हमारा जो पेट्रोलिंग वाला इलाका है, वह आज हमको उपलब्ध नहीं है। जब हम 750 किलोमीटर की बात करते हैं तो हमारा यही मतलब है कि 750 किलोमीटर में जहां पर हमारे सेना के पेट्रोल जा सकते थे, आज नहीं जा सकते हैं, क्योंकि चीनियों ने हमको रोक दिया है। हम खामोश हैं और हम अपनी सेना को आदेश को नहीं दे रहे हैं कि तुम मुकाबला करो। चीन की पॉलिसी है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं निबलिंग, जैसे चूहा धीरे-धीरे काटता है, वैसे Chinese are nibbling at the Line of Actual Control and they are re-drawing that Line. This is a very serious issue and in all humility, I will say that there is no politics. There is no politics because this is a matter of grave national importance. I, therefore, appeal to the Government with folded hands. Please come clean and please tell us what the truth is. Please tell us what is the challenge that we are faced with on the Line of Actual Control and the whole nation will be with you, will stand with you, if you take the strong action. यहां कहा गया है कि हमारी सेना कमजोर नहीं है। दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में हमारी सेना की गिनती होती है। उनको सिर्फ आदेश देने की ज़रूरत है। Therefore, it is not a question of any physical strength; it is a question of mental strength and it is a question of will power, political will power. I am appealing to the Government, Sir, through you, to the Defence Minister who is present in the House, to please develop that capacity, that courage to be able to meet the Chinese aggression headlong; give instruction to our Army to give them headlong.

I am quite sure, our very great and glorious Army will distinguish itself in this as they have done in the past. So, I want the Minister to tell the House what the truth is and assure the House that he will ask the Indian Army to do whatever it takes to meet the Chinese threat along the LAC. We will not sit quiet. This is my appeal to him and this is what I expect from him.

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): महोदय, माननीय यशवंत सिन्हा जी ने विस्तार से बता दिया है। इस सवाल को आज से नहीं, मैं चौदह साल से लगातार सदन में और सदन के बाहर बोल रहा हूं। मैंने सबसे मिलकर भी, हम नाम लेंगे, सत्ता में बैठे उच्च पदाधिकारियों से या मिनिस्टर जो भी हैं या प्रधानमंत्री जी तक मैंने इस बारे में बात की है और सावधान किया है। मंत्री जी, आप यहां बैठते थे, मैं रोज सावधान करता था और आपको बताता था।...(<u>व्यवधान</u>) यह बात सही है, ऐसा नहीं है मंत्री जी सच बोल रहे हैं। चीन के बारे में हमने कहा कि इतना धोखेबाज दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है। यह मैं कह रहा हूं। ...(<u>व्यवधान</u>) मैंने यहां कहा था कि नेहरू जी की मौत केवल चीन के कारण हुयी, मैंने यहां ऐसा कहा था। आपको याद होगा कि लोहिया जी ने लेख लिखा था तो तब कहा था कि नेहरू जी को जो धोखा हुआ है, चीन ने धोखा दिया है, चाउ एन लाई ने धोखा दिया है, वह सदमा उनको लगा, वे उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका निधन चीन की वजह से हुआ, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कई बार सावधान किया कि इस बात को गंभीरता से लीजिए। यह देश का सवाल है, यह देश के स्वाभिमान का सवाल है और आप दुनिया में हिन्दुस्तान को किस तरह से अपमानित करने जा रहे हैं। हमारा जो सम्मान है, जो सम्मान बढ़ रहा था, हमारा बड़ा देश है, विशाल देश है और जैसा मैं कई बार कहता हूं कि हमारी सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेना है। हमें अपने देश की सेना पर गर्व है। सेना के बड़े जनरल तक से कई दौर में मेरी बात हुयी। उन्होंने कहा कि नहीं देते, नहीं देते हैं हुक्म हमको। रक्षा मंत्री जी, आप साफ जवाब दीजिए। हर सप्ताह में सुरक्षा की रक्षा संबंधी देश की सीमा संबंधी मीटिंग होती है। आपने यह मीटिंग हर हफ्ते चलायी या नहीं। जब हम रक्षा मंत्री थे, तो हर हफ्ता मीटिंग करते थे। हमसे पहले कांग्रेस के रक्षा मंत्री थे, तब वे हर हफ्ता मीटिंग करते थे, बीजेपी के रक्षा मंत्री थे, तब हर हफ्ता मीटिंग होती थी। मेरे से एक अधिकारी ने स्वीकार किया था कि मीटिंग होती है। फिर मैंने सेना के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी से पूछा, मैंने कहा कि क्या यह सच है, यह आज से डेढ़ साल पहले की बात है, एक फंक्शन में हम मिले थे, उन्होंने कहा कि यह सच है। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमें हुक्म ही नहीं देते हैं। मैंने कहा कि हर हफ्ते मीटिंग होती है और उसमें जनरल रहता है तो उन्होंने कहा कि मैं रहता हूं और मैं कहता हूं। मैंने कहा कि क्या जवाब मिलता है, उसमें प्रधानमंत्री जी रहते हैं, रक्षा मंत्री जी रहते हैं, मैंने कहा कि क्या जवाब मिलता है तो उन्होंने कहा कि मौन, आज तक हमें कोई निर्देश नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते, हर मीटिंग में हम बात रखते हैं कि चीन हम पर कब्जा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अनजान हों। यह क्या कमजोरी है, आप इस बारे में बतायें। हम कह रहे हैं कि इस मामले में यह पूरा सदन, पूरे देश की जनता साथ है। कमजोरी किस बात की है? हमारी फौज कमजोर नहीं है।

<u>21.00 hrs.</u>

हम भी रक्षा मंत्री रहे हैं। अपने पुराने अधिकारियों को बुलाकर पता लगा लीजिए। चीन ने एक किलोमीटर पर निशान लगा दिये तो मैंने तीनों जनरल को बुलाकर कहा कि सावधान हो जाइए, और चार किलोमीटर पर निशान लगाइए तो हमने चार किलोमीटर पर निशान लगा दिये। आप पूछ लीजिए। उसके बाद एक दिन भी चीन एक इंच आगे नहीं बढ़ पाया, वह कुछ नहीं बोला। आज मैंने चीन के बारे में बता दिया है। उधर वह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रहा है, कश्मीर की तरफ से प्रवेश कर रहा है। कई जगह से प्रवेश करने की योजना वह बना चुका है, मैं सदन में कह चुका हूँ। वह चारों तरफ से हमें घेर रहा है। उसके बाद यह सरकार सारा सामान चीन से खरीद रही है। आर्थिक दृष्टि से हिन्दुस्तान चीन को मज़बूत कर रहा है। बाज़ार में छोटे-छोटे खिलौने तक सब चीन के आ रहे हैं।

MR. CHAIRMAN : Mulayam Singhji, please take your seat for a while.

Hon. Members, the time now is 9 p.m. If the House agrees, we will extend the time of the sitting by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Mulayam Singhji, please continue.

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सिन्हा साहब ने बहुत अच्छा किया और आपने बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया है। मैंने बताया कि चीन ने नेहरू जी से लेकर सबको धोखा दिया है। आज मैं फिर सदन में बता रहा हूँ कि चीन हिन्दुस्तान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है और जब मौका पाएगा तब हमला करेगा। रक्षा मंत्री जी बताएँ कि यह बात सच है या गलत है। अगर सच है तो आपने क्या किया? आप कहेंगे कि कोई खतरा नहीं है। सवेरे भी कह गए, फिर कह देंगे लेकिन इससे हम सदन के लोग सहमत नहीं होंगे। आपके भी कई लोग बैठे हैं। उनको पता है, वे भी चिन्तित हैं। आपको चिन्ता क्यों नहीं हुई? हम तो आपसे कई सालों से कह रहे हैं कि मैं इनकी बहुत इज्ज़त करता हूँ। यहाँ सिन्हा साहब कहते रहे, हमने आपको राय भी दी। आपके साथ बैठकर आपको कहा कि यह करिए, वह करिए, दिक्कत हो रही है, चीन ऐसा कर रहा है। आपकी मजबूरी क्या थी वह मैं जानना चाहता हूँ। मजबूरी किस स्तर पर हुई, वह मैं जानना चाहता हूँ। सेनापतियों से मजबूरी नहीं हुई। जब मीटिंग हर हफ्ते हुई है और हर मीटिंग में उन्होंने रखा है तो आपने पालन क्यों नहीं किया? सिन्हा साहब, हर हफ्ते देश की रक्षा संबंधी मीटिंग होती है। मैं रक्षा मंत्री रहा हूँ। और कोई मीटिंग पोस्टपोन हो, लेकिन यह पोस्टपोन नहीं होती है। उसमें जनरल पूरी सच्चाई से सब बात रखते हैं और उसका पालन होता है या नहीं। यह बताएँ कि क्या जो जनरल हैं, उन्होंने आपकी मीटिंग में यह बात कही या नहीं कही कि चीन से खतरा है और चीन हमारी ओर बढ़ रहा है? अगर उन्होंने नहीं बताया है तो पता चल जाएगा। अगर बताया है तो आपने क्या किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया?

महोदय, आज स्थिति ऐसी बन गई है कि चीन आगे बढ़ा और चीन पहले ही 1लाख वर्ग किलोमीटर पर कब्ज़ा कर चुका है। अभी जो कब्ज़ा किया है, यह ध्यान रखना कि मैंने आपको सावधान किया था कि चीन के पहले वे कैम्प वाले हट गए। लेकिन वे पूरे का पूरा देख गए कि कैसे हमला करेंगे, कहाँ से प्रवेश करेंगे, पहाड़ों से होकर कैसे आएँगे और कैसे हिन्दुस्तान को कब्ज़े में करेंगे। यह मैंने यहाँ सदन में कहा था और वह कार्यवाही में है कि वे रास्ता देख गए हैं, तैयारी कर गए हैं। ऐसा मत सोचो कि वे चले गए हैं। जब सड़कें बन रही थीं तो मैंने आपको सावधान किया था। मैंने यह भी पूछा था कि जब चीन सड़क बनवा रहा था तो हमने भी जो सड़कें बनवाई, उन सड़कों का क्या हुआ यह बता दो। आप यह बता दो कि हमने सड़कें बनवाई थीं या नहीं? जब सड़कें बनवाई और हमारी सरकार नहीं रही तो वे सड़कें जो अधूरी बनी हुई थीं, उनका आपने क्या किया? कितनी मरम्मत करवाई? नहीं करवाई तो मरम्मत क्यों नहीं करवाई? वे तो उखड़ गई होंगी। उस पर ध्यान नहीं दिया। कोई परवाह नहीं की तो देश को चला कैसे रहे हैं?

हमारी सेना बहादुर है और यह सही है कि दुनिया में सबसे बहादुर सेना है, सबसे ज्यादा कुर्बानी करने वाली सेना है। दुनिया में भेजी गई और देशों की रक्षा के लिए और बहादुरी से काम करके दुनिया में नाम करके आयी है। सभी जगह हमारी सेना गई। सेना हमारी मजबूत, सेना हमारी बहादुर तो कमजोरी कहां है। मैं यह कह रहा हूं कि सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि सरकार कनफ्यूज़न में कभी कोई क्लीयर हुक्म नहीं देती है। आप किसी अधिकारी से चुपचाप पूछ लेना, अगर विश्वास का हो, तो सेना के वरिष्ठ अधिकारी बता देंगे कि सरकार ने आज तक स्पष्ट कभी भी कोई निर्देश नहीं दिया। आप सेना को दुविधा में रखेंगे। अगर सेना को दुविधा में रखेंगे तो देश को आप बचा नहीं सकते हैं। सेना को यह क्लीयर होना चाहिए कि हमारे रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार क्या चाहती है? अभी तक इस सरकार ने सिन्हा साहब मैसेज नहीं दिया है कि हम क्या चाहते हैं कि हमारी सीमा सुरक्षित रहे, हमारी सीमा में कोई कदम बढ़ाने न पाए। आज तक क्या स्पष्ट निर्देश दिया गया है, मैं पूछना चाहता हूं। जब निर्देश नहीं दिया है तो सेना क्या करेगी? सेना तैयार है कि हम खदेड़ देंगे। मुझ से एक जनरल ने कहा था कि मुझे आप कहिए, उन्होंने मुझ से कहा था कि आप सदन में इतना भाषण दे दो, चीफ जनरल ने कहा था कि आप यह भाषण कर दो कि जो सड़कें मैंने बनवायी थीं उनका क्या हुआ? उसके कहने से मैंने सदन में आपसे डेढ़-दो साल पहले पूछा था, आप कार्रवाई देख लीजिए। उन सड़कों का क्या हुआ? हम लोग तो आपको सावधान करते हैं और आपका साथ दे रहे हैं। इस मामले में देश की जनता और पूरा सदन आपके साथ है, फिर रक्षा मंत्री जी क्या कमजोरी है? कमजोरी क्यों है? क्या आप लड़ेंगे, आप तो लड़ाएंगे। अगर आप डर रहे हैं तो वह बात अलग है। सेना लड़ेगी, आप तो जाकर नहीं लड़ोगे। वहां जो कुछ होगा, कुर्बानी वह करेंगे, शहीद होंगे या मारेंगे भी। यह क्या है, आप इसे गम्भीरता से नहीं ले रहे हो। आप जैसे लोग गम्भीरता से नहीं लेंगे, तो देश को फिर कैसे बचाएंगे? मैं इसीलिए सख्त होकर बोल रहा हूं और देसी भाषा में बोल रहा हूं ताकि आपका दिमाग ठनके। मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी। मैं भी तो रक्षा मंत्री रहा हूं। पाकिस्तान ने क्या नहीं किया था? हमने उन्हें खदेड़ दिया था। उसकी सीमा के अंदर मैदान में, लाहौर वाले मैदान तक हमारी फौज ने क्या कार्रवाई नहीं की है? पता लगा लेना आप। उसने हमारे जवानों का हेलीकाप्टर गिरा दिया था। मैंने उसका प्रचार कर दिया सदन के अंदर कि दुर्घटना हुई। मैंने ऐसा जवाब दिया था और सारे कश्मीर के उस समय के सातों पार्लियामेंट मेंबर्स मिलकर मुझे बधाई देने गए थे कि आपने पहली बार जवाब दिया पाकिस्तान पर। उस दिन से पाकिस्तान कभी भी हमारे समय में उंगली नहीं उठा सका। हमारा हेलीकाप्टर गिरा दिया था हमारी सीमा में, फिर हमने क्या किया था, पता लगा लेना और यहां मैंने कह दिया कि दुर्घटना हुई। नहीं बताया कि पाकिस्तान ने गिराया, मैंने प्रचार दुर्घटना का किया। सेना में हिम्मत है, अगर हमारे रक्षामंत्री, प्रधानमंत्री और सरकार में हिम्मत है, तो हमें चीन भी पीछे नहीं कर सकता है। हमारा एक सैनिक उनके तीन सैनिकों के बराबर है। तीन के बराबर है।...(व्यवधान) इतनी बहादुर सेना है हमारी। अगर वे कुश्ती भी लड़ें, तो तीन को उठाकर पटक देंगे। हां, ऐसा हुआ है। जब हथियार नहीं थे 1962 की लड़ाई में, तो बेचारे पटक-पटककर ही लड़े थे।...(व्यवधान) हमारे भाई साहब थे वहां, हमें इसीलिए यह सब जानकारी है। वह बच गए थे। हम से पूछिए सेना के बारे में, अभी हमारे परिवार के चार लोग हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अभी समय है, आपके साथ पूरा सदन है, जनता आपके साथ है। चीन पर कभी विश्वास मत करना और चीन को हिम्मत के साथ जवाब देना, यही अब एक उपाय है। हम सब लोग आपके साथ हैं। आप जिस तरह की भी मदद चाहोगे, मदद करेंगे। जनता में भी विश्वास भरेंगे। देश के सवाल पर हम आपके साथ हैं। हिम्मत से रक्षा मंत्री जी और सरकार के यहां बैठे मंत्रीगणों से कहूंगा कि चीन को जवाब दीजिए। अगर आप चीन को जवाब देंगे तो चीन आपकी सीमा के पास नहीं आएगा। जितना ही आप चीन से डरेंगे, उतना ही चीन आपकी सीमा के भीतर घुसता जाएगा। चीन के ये पांच हजार साल के संस्कार हैं। जब चीन कमज़ोर देख लेता है तो हमला करता है और जब देखेगा कि हिन्दुस्तान मज़बूती के साथ खड़ा है तो चीन भाग जाएगा। यह पांच हजार साल का इतिहास है।

इसलिए हिम्मत के साथ आप एक बार चीन का मुकाबला कर के दिखाइए। हम सब आपके साथ हैं।

MR. CHAIRMAN : Thank you. Hon. Members, please be very brief. Prof. Saugata Roy.

...(*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Mr. Chairman, Sir, I shall be very very brief since I am neither a former External Affairs Minister nor a former Defence Minister. I shall also not indulge in competitive jingoism saying that we are ready to go to war. It is very irresponsible to make a statement in this Parliament to say that, "Ask your soldiers to go and clear the Chinese." We are a big nation and we have to take all decisions carefully.

I am sure, knowing Shri Antony that I know for a long time, that he will not take any hasty action. This whole discussion is regarding the reported Report by Shri Shyam Saran, former Foreign Secretary and Chairman of the National Security Advisory Board. I want to know from the hon. Defence Minister whether Shri Shyam Saran had really said that China has occupied 640 sq. kms. of our territory or it is the figment of some reporters' imagination.

The second question is this. ...(*Interruptions*) The whole discussion is about the preparation of infrastructure along the border. Does he, as Defence Minister, feel that our infrastructure on the Chinese border, in Ladakh, is up to his satisfaction, up to the mark? Or does it need more improvement?

Lastly, we have a large border with China. In the west, starting from Ladakh, Aksai Chin right up to Uttarakhand, we have a border with China. If you come to this side, starting from Sikkim, Bhutan up to Arunachal we have a border with China. Now, there have been continuous border talks with China, both in Beijing and in Delhi. Shri Shiv Shankar Menon was heading our team for border discussion. I want to know from the hon. Defence Minister whether the border has been delineated. If not, by when he hopes, that through these talks, the border will be delineated?

India and China are two big nations. Both are nuclear nations. We cannot clearly afford to fight. We cannot also afford to make irresponsible statements.

Our great leader, Jawaharlal Nehru, made a one small statement, which I do not think was irresponsible and historians also do not think it was irresponsible. To a question in this very Lok Sabha about Chinese incursion, he just said: "I have told my soldiers to drive them out." What happened? On 20th October, 1962, China launched the massive invasion and Bomdila Sela Pass fell. It is all known to us. It has been called a colossal failure, a Himalayan blunder. We should not get into any action which will weaken India's prestige. Every action should be thought out.

I am sure, knowing the Defence Minister that I do, that he will take considered decision in keeping with India's position as a big nation, as a responsible and as a peace-loving nation.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति जी, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस गंभीर सवाल पर जो चर्चा हो रही है, ...(व्यवधान) यह चर्चा तब आयी, जब कल हाउस के दौरान इस सदन को माननीय जसवंत सिंह जी के द्वारा यह सूचना दी गयी, कहीं मीडिया से उनको यह सूचना मिली कि चीन की सेना हमारे देश में 640 वर्ग किलोमीटर अंदर चली आयी है।

सभापति महोदय, सवाल केवल सीमा में घुसने का नहीं, अतिक्रमण का नहीं, बल्कि देश की अस्मिता का सवाल है। इस देश का इतिहास गवाह है कि जब-जब इस देश की सीमा पर अतिक्रमण करने का अगर किसी विदेशी ताकत ने प्रयास किया तो हमारे देश की सेना ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश की सीमा की सुरक्षा की है। सदन में ऐसे मौके कम आते हैं, जब पूरा सदन एक साथ अपने सरहद की सुरक्षा में खड़ा होता है। आज पूरा देश इसके लिए खड़ा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि चीन द्वारा बार-बार सीमा पर अतिक्रमण को लेकर जो सवाल खड़े किए गए, मंत्री जी की तरफ से जवाब दिया गया और उसके बाद भी हमारी सीमा से सटे देश चाहे जो भी हों, अगर वे हमारे देश की सीमा पर अतिक्रमण करते हैं, जैसी सूचना मीडिया के माध्यम से मिल रही है, तो मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही जानना चाहता हूं, हम केवल जवाब के लिए नहीं, हम कार्रवाई चाहते हैं कि आप आने वाले दिन में क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? यह सदन और देश जानना चाहता है।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Mr. Chairman, Sir, we are discussing the nation's security. We are discussing the Chinese attempt to encroach upon our border area.

Sir, there are many reports in this connection. We are reading in the newspapers and we come to know from the media that China is making an attempt to encroach upon our territory. Also, recently, the hon. Defence Minister said - I read two days back in the newspapers - that the territory issue between China and India is not yet settled. Somewhere in a function,

the hon. Minister said this. I read yesterday in the newspapers.

In this connection, I want to know from the hon. Minister the real situation. What is our stand? What is our position now regarding the territory? Are we still having dispute with China? I pose this question because China is claiming so many areas of our Indian territory as its territory. We are against that.

Also, Sir, it is not only the territorial issue. For example, on the economic side also, China is entering our Indian market. A lot of goods are coming from China to India. In the name of trade, they are dumping all the goods here. As the British came once, China is also doing the same thing....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please confine to the issue that we are discussing.

DR. M. THAMBIDURAI : I want to tell how China is moving. It is moving in the same way the British people came for trade. Afterwards, they conquered India, ruled this country for about 200 years. We struggled for freedom. Therefore, apart from the military action, China is encroaching upon the Indian market also. That is a very serious and dangerous thing. Further, we have to know how China is developing friendship with the neighbouring countries like Pakistan and Sri Lanka. We know very well that after the dispute started about *Katchatheevu* and other things, what Sri Lanka s doing is that it is threatening India by way of extending an invitation to China to establish certain bases in Sri Lankan area also. That is another way of coming. In Pakistan, they are moving. In Bangladesh also, they are trying it. They are trying in Myanmar also. Why I am telling is that apart from the military action, China is developing friendship and it is trying to surround India. That is a serious matter. That is why I am requesting the hon. Defence Minister to take all these kinds of facts seriously. At the same time, Sri Lanka also must not exploit the situation.

China is behaving like a friend but at the same time, they are trying to indulge in incursion in the Indian territory. Therefore, I would request the hon. Minister to make a clear statement as to what is the position. What is the intention of China? Is China really a friend? In the name of friendship, China is indulging in all sorts of inimical activities. It is a very serious matter. Hence, I would request the hon. Minister to clarify.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सभापति महोदय, पन्द्रहवीं लोक सभा में कई बार चाइना के इश्यू के बारे में डिसकसन किया गया है। बार्डर इश्यू पर कई दफा डिसकस किया गया है। डिसकसन करने के बाद माननीय मंत्री जी ने पहले भी स्टेटमेंट्स दिए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से हाउस को और पूरे देश को एश्योरैंस भी दिया गया है। There is no border issue with China. अभी हाल में जब 750 स्कवायर किलोमीटर अकुपेशन का इश्यू आया तो, इस हाउस में तीन-चार दिन पहले इस पर डिसकस करने के बाद, पूरे सदन ने माननीय मंत्री जी के स्टेटमेंट की मांग की। फाइनली, माननीय रक्षामंत्री जी ने स्टेटमेंट दिए। माननीय रक्षामंत्री ए. के. एंटोनी साहब आदरणीय व्यक्ति हैं। हम लोगों ने आशा की थी कि ऐक्चुअल पोजिशन स्टेटमेंट में आएगी। इस स्टेटमेंट में यह बहुत स्पष्ट है। इस स्टेटमेंट में तीन पैरा हैं। पहले पैरा में, चेयरमैन श्याम शरण उधर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए गए थे।

दूसरे पैरा में, यह स्पष्ट है कि उसका प्रोग्रेस रिव्यू कर के, उधर रोड चाहिए, टनल चाहिए, क्या करना है, यही दूसरे पैरा का मीनिंग है।

तीसरे पैरा में चाइना के बारे में नहीं है। श्याम शरण जी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर रिव्यू करने के लिए गए हैं। पर्टिकुलर इश्यू जो हाउस में डिसकस हुआ है, उसके बारे में रिपोर्ट दी है, अगर वह रिपोर्ट दी है, तो गवर्नमेंट रिपोर्ट में नहीं लिख पाई है। व्हाइट पेपर के साथ, फैक्चुअल पोजिशन देश को बताने की जरूरत है, अगस्त हाउस को बताने की जरूरत है, जो इंटरनल बात हुई है। हमें एंटोनी साहब पर बहुत विश्वास है। हम उनके रिप्लाई में ओपेन हार्ट से व्हाइट पेपर रिलीज करने के लिए मांग करते हैं।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Yesterday, hon. Defence Minister made a statement and the question arises out of some news published in the newspapers with regard to Shri Shyam Saran's report. Even today, after the Statement by the Minister, some doubts have been raised. So, I think, the Minister should clear everything. But I want to mention three points.

Firstly, what about the construction of infrastructure in the border area of our country? What are the defects? How far are they going to implement their programmes? What are the programmes?

Secondly, we are proud of our military forces; we are proud of our Armed Forces. We should see that their morale should be protected; they should not be demoralized. But that does not mean that jingoism is the answer. We should ask our military forces to combat the Chinese forces.

This question has arisen at a time when both the Armies are talking with each other on the border dispute. I think the Government is also initiating a discussion on the border dispute and we are very hopeful in this regard.

My last point is that the Minister should clearly state the position to remove the doubts of the hon. Members of this House

as to what is the status on the Line of Actual Control at this moment so that all sorts of confusion can be removed.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Mr. Chairman, Sir, I will just take two minutes only. I want to add to what hon. Member Shri Yashwant Sinha said. He referred to the Ladakh area. But I want to mention about Arunachal Pradesh about which I raised earlier also on the 18th of August. China intruded eastern Arunachal Pradesh in the Pompom area which is 400 kms. from Tinsukia. There is motorable road from Tinsukia which goes only up to Changlang area. Beyond that there is no motorable road and the soldiers have to walk 105 kms. up to the border. Our BJP volunteers, after this intrusion of China on 10th August, occupied the First Outpost, then the Second Outpost, the Third Outpost and also the Fourth Outpost. They covered 55 kms. of Arunachal Pradesh and then they returned on their own. There is no proper border, only ITBP forces are there. Very rarely they visit the area and then they come back. There is no road and our Army *jawans* have to walk for 15 days covering 105 kms. On the Chinese side, there are roads, there is an airfield etc. After 51 years of Chinese aggression of 1962 and *Hindi-Chini Bhai Bhai* days, China crossed 400 kms. into Arunachal Pradesh just entering Assam border and then they went back. After 51 years of Chinese aggression in 1962, why is there no proper border? The people of Arunachal Pradesh are in a very terrible state. Are you going to present Arunachal Pradesh to China? Why is there no proper Border Post? Why have you not allowed the Army to work and fight there? I request the hon. Minister to answer these points. ...(*Interruptions*) The Chinese Army entered in the Pompom area of Arunachal Pradesh and he knows it. I am not going to politicize this issue. The Minister should answer my question.

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Mr. Chairman, Sir, keeping in view the circumstances at the moment, I would like to say that there is an international border intrusion in Manipur by the Myanmar Army. Recently, a team from the Government of Manipur has gone there and the Government of India also has sent its team. But now it is reported that the people of Holenphai village near the International Border Pillar No. 76 are asked to vacate the area as the Myanmar Army wants to have a Post there. I want to draw the hon. Minister's attention to this fact.

सभापति महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, क्या आपको एक प्रश्न पूछना है?

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): जी हां, मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा।

माननीय सभापति महोदय, यशवंत सिन्हा जी, माननीय मुलायम सिंह जी, सौगत राय जी, तम्बिदुरई

जी आदि जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। माननीय मुलायम सिंह जी जब रक्षा मंत्री थे, उस वक्त जब सीमा पर खतरा हुआ, उन्होंने सीमा पर जाकर बहादुरों की हौसला अफजाई की, मुकाबला करवाया। मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि लद्दाख पर चीनी सेना की बराबर घुसपैठ हो रही है। क्या आप लद्दाख गए? आपने सेना के लोगों का मनोबल बढ़ाया? आप वहां जाने का काम करेंगे या आपकी इच्छा शक्ति मर गई, यह आप बताने का काम करें।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जानता हूं कि रक्षा मंत्री जी इसका पूरा जवाब देंगे। चूंकि यह मेरे क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए मैं घुसपैठियों के विषय में दो शब्द बोलना चाहूंगा। कुछ दिन पहले खबर आयी थी कि हमारे क्षेत्र चाकलाहांग में घुसपैठ हुई थी। उसमें अनजाऊ डिस्ट्रिक्ट है, जो बहुत दूर-दराज का एरिया है। वहां अभी भी सड़क और यातायात की सुविधा में कमी है। सदन के सभी सदस्यों ने जिस प्रकार हमें सहमति दी, जिस प्रकार उन्होंने हमारा ध्यान रखा, खासकर हम एक्स डिफैंस मिनिस्टर और प्रतिपक्ष के नेता का बहुत आभार प्रकट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे वहां के जितने भी नौजवान हैं, सीमा एरियाज़ में, चाहे आईटीबीपी के जवान हैं, चाहे एसएसबी, आर्मी के जवान हैं, वे सब अभी सशक्त हैं, बहुत ही सतर्क हैं। मैं खुद उन एरियाज का मुआयना करके आया हूं और मैंने वहां के जिला प्रशासन से बातचीत भी की है। उनकी जो पैट्रोलिंग होती है, जिसे हम घुसपैठ कहते हैं, शायद उसमें कुछ लोग जो चीन के फौजी हैं, वे आये थे, ऐसी बात नहीं है कि वे नहीं आये थे। लेकिन उन्हें आने में कम से कम दो दिन लगते हैं और वापिस जाने में भी दो दिन लगते हैं। इस तरह शायद चार दिन लगे हों। वह बहुत ही घना जंगल हैं। हम चाहते हैं कि चीन के साथ हम अपना दोस्ती का हाथ बढ़ायें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि चीन हमारे ऊपर दबदबा डाले, चीन हमें डराए-धमकाएं। हम जानते हैं कि हमारे जितने जवान हैं, फौज हैं, वे पूरी तरह तैनात हैं और हम भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे वहां के जो देशभक्ति के प्रतीक हैं, देश के पक्ष में हैं, उन्हें आपको सलाम करना होगा। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि हमने देश भक्ति की प्रेरणा जो आप सबसे पायी, चाहे पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी या विपक्ष के हमारे जो नेता थे, उनको भी हम सलाम करते हैं। हम भारत का एक अंग हैं और हमारी जो देश भक्ति की भावना है, वह सदा हमारे देश के लिए रहेगी।

MR. CHAIRMAN : Now, the hon. Defence Minister.

...(*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, please allow me to speak for a minute...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Karunakaran, we had a long discussion. You were absent in the House; I was looking for you. Please cooperate. All the important points have been brought before the House.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: All right. Please be brief.

2

SHRI P. KARUNAKARAN : Sir, I am really thankful to you. The hon. Defence Minister had made the Statement in the House. I think that hon. Defence Minister has got the records and evidence which he has corrected and placed before the House. At the same time, there are reports that China has crossed the Line of Control and whether it is correct or not is not possible to say now. No doubt, the security and safety of the nation is the most important, but at the same time, we should not take a hasty step and we have to realize whether it is correct or not. So, such a patient stand has to be taken. I am sure the hon. Defence Minister is capable of doing that. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Yes, the hon. Defence Minister, please.

...(*Interruptions*)

डॉ. बलीराम (लालगंज): सभापति महोदय, आप मुझे भी एक मिनट बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No, please. Mr. Dara Singh has already spoken. Please take your seat.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. Now, the hon. Defence Minister, please.

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI A.K. ANTONY): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to all the hon. Members for giving the valuable suggestions regarding protection of our border. While discussing, naturally, some of the Members became a little annoyed with the Government. I can understand that.

One thing I would like to say at the very beginning. Today's discussion is not an extensive discussion on India-China border. My statement was to a limited issue raised regarding a reported report given by Shri Shyam Saran to PMO. The report came in some of the Mediums. According to the media reports, Shri Shyam Saran, after visiting Ladakh, gave a report to PMO that China encroached and occupying 640 kms. of Indian territory. That was the question raised, I gave a very factually hundred per cent honest factual report. That report was like this: "I would like to state categorically that Shri Shyam Saran has not stated in this report that China has occupied, or has denied access to India to any part of Indian territory." That is factually correct. That is the report; there is no mention about that in the report. I can corroborate that.

Even the author of the report, Shri Shyam Saran himself issued a statement yesterday. The Chairman of NSAB, Shyam Saran, has denied media reports that he has submitted an official report to the PMO accusing the PLA of occupying 640 sq. kms. of Indian territory. So, Shyam Saran himself said, I don't have such a report and the Government has no such report. So, without getting a report like that, how can I discuss about alleged Chinese occupation of that area? That is why, I gave factual report. There is nothing like changing the report; it is a genuine report.

Another thing is this. Shyam Saran himself said, "NSAB does not concern itself its operational matters. His concern was something else, how to improve the border infrastructure and other issues." That was in the report. So, I gave a brief report, a *suo motu* statement in the Rajya Sabha, here, in this House, as per the enquiry. It is a very brief report about a particular issue. My statement is not an elaborate statement about the India-China border. You see, India-China border issue is not a new one. India has a long border with China. Even though India has border with many other countries, our

longest border is with China. Every one of you knows that our border with China is not settled. My friend, Prof. Saugata Roy asked me whether it is delineated. It is not delineated. India-China border is not delineated. The entire area is unsettled. But, even though this entire area is unsettled, for vast areas, there is an agreement between China and India about the Line of Actual Control. There are some areas, in which, even today, there is no agreement between India and China about the line of actual control. These areas are known as disputed areas. In these areas both countries are sending their troops to patrol. China thinks that up to a certain areas their army should patrol. India thinks up to a certain area, it is theirs. In some pockets ITBP also used to petrol.

As Shri Yashwant Sinha ji mentioned in the beginning, it is correct that the patrolling limit was decided ultimately in 1976 by the Government of the day as to how to patrol and how far you must go. All these things were decided in 1976. After that, many Governments came and gone but, basically, this 1976 patrolling limit continued. Even, now our own troops are carrying regular patrolling up to that LoC. Then, some of my colleagues told me: "Does that mean that China does not occupy any Indian territory?" Yes, it is not now. Everybody knows that in the year 1962-63, in two years, there was occupation of Indian territory; in 1962, in Arunachal Pradesh and in 1963, in PoK. This is our legacy. It is occupied not now. It has happened 50 years ago. This dispute is going on. But that dispute is unsettled. After long years of negotiations, with both Governments, both Governments have decided that this long pending India-China boundary dispute should be settled. For that purpose two people were nominated, NSA from Indian side, and his counterpart from Chinese side. They are continuing with the negotiations to find solution to the border disputes. That negotiation continued during the NDA period and it has been continuing during UPA period also. It is continuing on the same pattern. Nobody has changed the pattern. The Governments change but not the pattern. Attempts are going on to find an everlasting solution to this long pending India-China border dispute. But it will take some time. You cannot expect miracles. In between a lot of things have happened. I have no hesitation in admitting the reality. China is much advanced in the area of building infrastructure in comparison to India. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching them. That is also a history. What is it? The independent India had a policy for many years that the best defence is not to develop the border. Undeveloped borders are safer than developed borders. So, for many years, there was no construction of roads or air fields on the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So, as a result, they have now gone ahead of us. Compared to us, infrastructure-wise, capability-wise in the border areas, they are ahead; I admit that. It is a part of history. But, of late, in the last 20-25 years, the Indian Governments also realised the mistake and changed its policy. Now, we are also strengthening our capabilities in the border areas. I do not dispute it. When Mulayam Singhji was the Defence Minister, he had also done a lot of things for developing the capabilities in the border areas, strengthening the Armed Forces. When NDA was there, they had also done a lot of things to strengthen the border areas and capabilities, and modernise the Armed Forces..

But I can tell you, without any exaggeration, that only during the last nine years, as the UPA Government, we have done the maximum to strengthen the capabilities in the border areas. In times of UPA-I & UPA-II, it is being done; and may be the future Governments also will continue the same thing; whoever comes, they will continue the same thing.

I cannot give all the details but I can tell you that after 29 years, our Government, four years ago, formed two Mountain Divisions in the border areas. So many airfields, so many ALGs and so many other developments are taking place. Of late, a few months back, our Government sanctioned strengthening of the border areas, another Force Accretion Project. People are calling it by many names. But actually, the idea is the Force Accretion. So, in the last many years, continuously, we are strengthening our Armed Forces.

So, the morale of the Indian Armed Forces, at the moment, is very high. That is why, when you talk about Depsang incident, that incident took place on 17/04/2013 and it continued up to 05/05/2013 for many days. But the Indian Army stood the ground. They did not withdraw. Ultimately, the issue was resolved when the Chinese PLA disengaged from the general area of Depsang Bulge.

So, our Army is now in a better positions; their morale is very high. But unfortunately, one thing is happening. What is happening is that in the earlier times, infrastructure development of both the countries was very slow. But over the years, China moved very fast. But now we are also catching up. So, India also is catching up in the infrastructure development. As a result, now in almost all the border areas, the Indian Army and the Chinese Army coming closer. Earlier it was not there. They were at a distance of about 1000 kilometres, but now, they are coming closer.

When the Chinese side comes to the areas of our perception, we say incursion; when our people go there, they say: "Our people are going there." Our patrols are also going up to the mandated areas everywhere. About some of the areas you mentioned that our patrols are not going. It is not true and factually correct that whether it is Depsang, or Pangong or Chumar, our patrols are going regularly. Even in Depsang, there was face-off. Now, our people are going there . We have not stopped the patrolling there. Our patrolling is decided by a Group consisting of various stakeholders, in which the Army

is a main voice. It was decided in 1976. That is continuing now. So, now both the sides are developing their capabilities. Even though earlier China had gone ahead, India is also catching up. So, there are many occasions. In the last many years, even face-off is taking place. They are coming closer but luckily for us, all these face-offs are peaceful. But both the Governments are now discussing how to avoid this. Both the armies are coming closer, face to face. How to avoid this kind of tensions? So, our understanding now is, let the Special Representatives continue their talks for finding a longstanding solution to the border dispute. Let them handle that part. Till a final settlement of the border issue is reached, our one point agenda is to maintain peace and tranquillity and stability in the India-China border without sacrificing an inch of our land which is protected.

So, the present negotiation, apart from Special Representatives, that we are having, our military is having is, how to maintain peace and tranquillity in the border areas. So, there are many mechanisms now but still this kind of incidents happen. It is not now, but for the last many years it has been happening. So, now we are discussing to find out new mechanism which can be more effective so that whenever an incident takes place, immediately both the militaries can intervene and solve the issue. That kind of confidence building discussion the military is having. Apart from diplomatic channel discussions, now we are encouraging from both the countries to have more military to military discussions for confidence building so that whenever issues are coming on the ground, the military, the local field officers can immediately intervene and sort them out.

I do not want to have a dispute with my respected colleagues. But the Government of India has not given any direction thereby our armed forces do not act. Whenever a situation arises in the border areas, they are free to handle it as per the situation demands. The local situations are handled by them only. Every year, every month lot of incidents are taking place. They are handling them. We are not giving direction. Even the Army Headquarters have not given direction. The local field people are handling. That is how, they are handling. Now, we are trying to find some more mechanisms, effective forums so that we can avoid this kind of unpleasant and unfortunate face-offs or other incidents.

So, our approach is three-fold. One is to find a longstanding solution to this border dispute between India and China through the mechanism of Special Representatives. Second one is to develop more mechanisms so that whenever dispute of incursions or occasional face-off takes place, immediately both the sides can intervene and sort it out. That is another part. While doing this, our Government is very clear on that. Since China has already gone ahead in infrastructure building, one thing we are very clear we will continue the process of strengthening our capabilities in the border areas. That is a clear policy. There is no question of compromising on our ability of strengthening our capabilities. We will not compromise on that. So, this is a three-fold strategy. We are going like that way.

There are issues. I agree with you but we have to find solutions. But we cannot, as responsible people, immediately overreact on the basis of a media report. Actually, that media report is not correct, according to the author of the report. Even Shyam Sharan says that I have not given such a report. So, how can a responsible Government of the day react over such a media report? That is why, we have acted like that. But I can assure the House that even though India is anxious to find the everlasting solution of the border issue; even India is anxious to avoid unpleasant incidents in the border areas, at the same time, at no point, Indian Government will compromise with the process of strengthening the capability and we will not compromise that an inch of Indian land be encroached by any foreign country. Regarding national security we are one. Let us send a message to the country and to the whole world that India is one regarding national security. It is what I meant.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Now, we take up Item No.7 - Shri Shailendra Kumar ji.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Mulayam Singh, please sit down. We will now go the next Item.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Yashwant Sinha ji, please sit down.

...(*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA : Is the Depsang Bulge is under our control, under our occupation or not? ...(*Interruptions*) The Minister is not answering. ...(*Interruptions*) The bulge was beyond the LAC. ...(*Interruptions*) The LAC included the bulge. ...(*Interruptions*) Now, what is the position of the Depsang Bulge? Are the Chinese coming in the Depsang Bulge; are they patrolling it? That is our territory. This is what I want to ask? ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please, do not make a noise. Before the hon. Minister reply this question, Mulayam Singh Yadav ji also

wants to ask one question. And, that is all. Then, there is no other question.

...(*Interruptions*)

SHRI A.K. ANTONY: First of all, I would like to answer the point raised by Shri Yashwant Sinha, regarding the Depsang Bulge, where the incident took place. We have told the China to maintain the status quo. The issue was resolved. The PLA disengaged itself from the area of Depsang Bulge. Our people have started going on. They are patrolling as per the mandate. I want to tell the House that actually this year itself our Army has gone to this area 27 times.

And, Shri Mulayam Singh is concerned. China is claiming vast areas of Indian land. But, not from now. As Yashwant Sinha ji said, in 1959, they had written a letter to the Indian Government. Since that time they are claiming on these areas. But, in 1959 itself, after receiving the letter, the Government of the day totally rejected their claim. So, they are still standing on their claim; we are rejecting their claim. Now, both sides are trying to find a solution to the issue.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Before I take the next Item, that is, Item no.27 - the 'Half an Hour Discussion', if the House agrees, we will extend the time of the House.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: We will extend the time of the House for of half an hour. This is 'Half an Hour Discussion'.

Shri Shailendra Kumar ji.